



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939

No. 3125]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

का.आ. 3565(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ छत्तीसवां संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,-

(क) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,-

(I) “क. आर्थिक कार्य विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 में, मद (ख) का लोप किया जाएगा।;

(II) “ग. राजस्व विभाग” उप-शीर्षक के अधीन,-

(i) प्रविष्टि 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“14. अधीनस्थ संगठन:

(क) आयकर विभाग;

(ख) सीमा-शुल्क विभाग;

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग;

(घ) स्वापक पदार्थ विभाग (इसके अंतर्गत स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो नहीं है);
और

(ङ) माल और सेवा कर प्रशासन।”;

- (ii) प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“17क. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) से संबंधित कार्य और संबंधित अंतर-मंत्रालयीय समन्वय।”;
- (iii) प्रविष्टि 18 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
“18क. माल और सेवा कर परिषद्।
18ख. माल और सेवा कर अपील अधिकरण।”;
- (iv) प्रविष्टि 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“21. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले -
(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12);
(ख) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13);
(ग) संघ-राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14);
(घ) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15);
और
(ङ) विधानमंडल रहित संघ-राज्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क को छोड़कर) से संबंधित विधायी कार्य।”;
- (ख) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. आंतरिक सुरक्षा विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 58 में, “आर्थिक कार्य विभाग” शब्दों के स्थान पर “राजस्व विभाग” शब्द रखे जाएंगे।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[मि. सं. 1/21/11/2017-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2017

S.O. 3565(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Sixth Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—
(A) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”,—

(I) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”, in entry 1, item (b) shall be omitted;

(II) under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)”,-

(i) for entry 14, the following entry shall be substituted, namely:-

“14. Subordinate Organisations:

(a) Income Tax Department;

(b) Customs Department;

(c) Central Excise Department;

(d) Narcotics Department (excluding Narcotics Control Bureau); and

(e) Goods and Services Tax Administration.”;

(ii) after entry 17, the following entry shall be inserted, namely:-

“17A. Work relating to the Financial Action Task Force (FATF) and related Inter-Ministerial Coordination.”;

(iii) after entry 18, the following entries shall be inserted, namely:-

“18A. The Goods and Services Tax Council.

18B. The Goods and Services Tax Appellate Tribunal.”;

(iv) after entry 20, the following entry shall be inserted, namely:-

“21. All matters relating to –

(a) The Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);

(b) The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);

(c) The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017);

(d) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017); and

(e) Legislative work related to Indirect Taxes (excluding Custom Duty) in Union Territories without Legislature.”;

(B) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)”, in entry 58, for the words “Department of Economic Affairs”, the words “Department of Revenue” shall be substituted.

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 1/21/11/2017-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.